Pradesh Government for Development of Handloom Sector in that State;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action/measures taken by the Union Government thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) On the basis of proposals received from the Government of Madhya Pradesh, the Central Government has released funds to the tune of Rs. 72.10 lakhs under Plan and Rs. 682.90 lakhs under Non-Plan during 1993-94 for Handloom Sector as below:—

(Rs. in Lakhs)

Sl.No.	Name of the Scheme	Amount Released During 1993-94
	PLAN	
1	Scheme for Grant of Margin Money to Destute Weavers . .	0.50
2	Integrated Handloom Village Development	11.60
3	Handloom Development Centres	20.00
4	Grant for Workshed-cum-Housing Scheme for Handloom Weavers	40.00
	TOTAL PLAN :—	72.10
	NON-PLAN	
1	Special Rebate/Market Development Assistance on sale of handloom cloth	103.70
2	Subsidy on Janata Cloth Scheme	579.20
	TOTAL NON-PLAN:—	682.90

Co-operative Cotton Yarn Mills in Madhya Pradesh

153. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the total number of mills manufacturing cotton yarn in Madhya Pradesh, operating in Co-operating sector;

(b) whether the raw material supplied to these mills are in short supply;

(c) if so, whether some of them have stopped working due to non-availability of raw material;

(d) if so, how many such mills are sick at present; and

(e) what proposals are being considered to revive these mills?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) There are two Co-operative spinning

mills manufacturing cotton yarn, in operation, in Madhya Pradesh.

(b) to (e) Mills are required to obtain their raw material through the normal market channels. No reports of shortage of raw material have been received from these mills.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED AND UNSTARRED QUESTIONS SET FOR THE 25TH JULY, 1994

कोल इंडिया लिमिटेड का योजना परिव्यय

*1. **श्री अजीत जोगी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोल इंडिया लि० के योजना परिव्यय हेतु पंजीगत व्यय के लिए 10,499 करोड़ रुपए की धनराशि देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो भूमिगत तथा खुले मुहाने की खानों (खुले मुहाने की शुरु की जाने वाली नई खानों सहित) के विकास के संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोकिंग कोल प्राप्त करने के लिए भूमिगत खानों का विकास करने हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) योजना आयोग ने आठवीं योजनावधि के लिए कोल इंडिया लि० के संबंध में 8520 करोड़ रु० (1991-92 की कीमतों पर) के परिव्यय की राशि की सिफारिश की है ।

(ख) इस संबंध में परिव्यय की कुल राशि में से 7122 करोड़ रु० की राशि को खनन परियोजनाओं पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है । इसमें भूमिगत खानों तथा ओपेनकास्ट खानों का अंश लगभग क्रमश: 28% तथा 72 का है । योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना के अंतिम वर्ष में ओपेनकास्ट तथा भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन क्रमश: 196.15 मि०ट० तथा 73.85 मि०ट० किए जाने की सिफारिश की गई है । आठवीं योजना के दौरान आरंभ की जाने वाली नयी कोयला खनन परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण I में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । केन्द्रीय आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० को कोककर कोयला उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए नई भूमिगत खानों के विकास को प्राथमिकता दिए जाने को कहा गया है । तदनुसार, चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त, भूमिगत एवं ओपेनकास्ट दोनों तरह की 22 कोयला खानों को कोककर कोयला के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए आठवीं योजना में विकास करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है । इन खानों के नाम विवरण-II में दिए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, केडला तथा मधुबंद वाशरियां कोककर कोयले की उपलब्धता में सुधार किए जाने के लिए कार्यान्वयनाधीन हैं ।

विवरण-I

कोल इंडिया लि० को (आठवीं योजना) की नई कोयला खनन परियोजनाओं की सूची

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1. नकराकोंडा (पुनर्गठन)
2. टीलाबोनी (पुनर्गठन)
3. चपुई खास
4. हुरा "सी"
5. चिता
6. गौरंगडीह ओ०का० "बी"

*The sitting of the Rajya Sabha on Monday, the 25th July, 1994 was adjourned as a mark of respect in memory of Snri N. E. Balaram. Answers to questions put down in the lists for that day were laid on the Table of the House on Tuesday, the 26th July, 1994.